



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २४]

बुधवार, जुलै १५, २०१५/आषाढ २४, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १५ जुलाई २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXXII OF 2015.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL
CORPORATION ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३२, सन् २०१५।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और, इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश,

सन् १८८८ २०१५, १५ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;
का ३ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, सन् २००५
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :- का महा.

अध्या. क्र.

१३।

संक्षिप्त नाम और १. (१) यह अधिनियम, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

प्रारम्भण ।

(२) यह १५ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन १९८८ का २। २. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा १४०क सन् १८८८
में, चतुर्थ परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :- की धारा
१४०क में

परंतु यह भी कि, १ अप्रैल २०१५ से प्रारम्भ होनेवाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए, ४६.४५ वर्ग मिटर संशोधन।
(५०० वर्ग फीट) या कम चटाई क्षेत्रवाले आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में उद्ग्रहणीय
संपत्ति कर की रकम, ३१ मार्च २०१५ से ऐसे आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में जो उद्ग्रहित
की जाएगी और देय होगी, वह संपत्ति कर की रकम से अधिक नहीं होगी ”।

सन् २०१५ का ३. (१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५

महा. अध्या. क्र.

१३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के का महा.
अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा अध्या. क्र.
संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी १३ का
निरसन
तथा
व्यावृत्ति।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम ने, १ अप्रैल २०१० से भवनों तथा भूमियों के उनके पूंजीगत मूल्य के आधार पर बृहन्मुंबई में संपत्ति कर की उद्ग्रहण प्रणाली को अंगीकृत किया है।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १४०क का चतुर्थ परंतुक यह उपबंध करता है कि, आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकृत वर्ष से प्रारम्भ होनेवाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए, धारा १४०क के अधीन संपत्ति कर के उद्ग्रहण के लिए ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या कम चटाई क्षेत्र वाले आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में, उद्ग्रहणीय संपत्ति कर की रकम आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकरण के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में, उद्ग्रहित की जायेगी और देय होगी वह संपत्ति कर की रकम कम नहीं होगी। उक्त धारा १४०क की उप-धारा (१) का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि, संपत्ति कर के आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य को निगम ने अंगीकृत करने के पश्चात्, किसी कराधेय भवन के संबंध में संपत्ति कर, प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात्, पुनरीक्षित की जाएगी और ऐसे प्रत्येक पुनरीक्षण पर संपत्ति कर की ऐसी रकम ऐसे पुनरीक्षण के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में उद्ग्रहित की जायेगी और देय होगी, वह संपत्ति कर के चालीस प्रतिशत से किसी मामले में अधिक नहीं होगी। उक्त चतुर्थ परंतुक के उपबंधों की दृष्टि से, आवासीय भवन या आवासीय वासगृह के संबंध में संपत्ति कर के ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) का चटाई क्षेत्र होगा, संपत्ति कर के उद्ग्रहण के लिए आधार के रूप में पूंजीगत मूल्य के अंगीकरण के दिनांक से पाँच वर्षों के अवसान की अवधि तक १ अप्रैल २०१५ से पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

२. राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया था कि १ अप्रैल २०१५ से पूंजीगत मूल्य आधार पर संपत्ति कर के पुनरीक्षण के पश्चात्, संपत्ति कर जो सभी भवनों तथा भूमियों पर उद्ग्रहणीय और देय हैं वह ४० प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। यह भी सरकार के ध्यान में लाया गया था कि, लघु वासगृहों या आवासीय भवनों के अधिभोगी जो कि ऐसे लघु वासगृहों या आवासीय भवनों के नये अधिभोगी, थे वह ऐसे पुनरीक्षण द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना हैं।

यह भी ध्यान में लाया गया था कि, राज्य सरकार तथा नगर निगम की विभिन्न योजनाओं के अधीन पहले से ही ज्यादातर ऐसे लघु आवासगृहों या आवासीय भवनों को विकसित किए जाने के कारण निम्नतर संपत्ति कर के लाभ को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है। मुंबई नगर निगम ने ऐसे लघु आवासगृहों या आवासीय भवनों को निम्नतर संपत्ति कर का लाभ दिलाने के लिए एक संकल्प भी पारित किया है। अतः उक्त प्रयोजन के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १४०क में यथोचित संशोधन करना आवश्यक हुआ था।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्यादेश क्रमांक १३), १५ जून २०१५ को प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १० जुलाई २०१५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

मुंबई,
दिनांकित १३ जुलाई २०१५।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १५ जुलाई २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।